ARRIVAL OF THE FIRST BATCH OF ENRICHED URANIUM FROM FRANCE

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now Mr. Shivraj Patil will make a statement.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.

ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : Sir, I am happy to inform this august House that the first batch of enriched uranium from France has just landed at Hyderabad Airport. The material is being moved to the Nuclear Fuel Complex at Moula Ali and the trans-shipment to the factory should be completed by this evening. Weighment and cofirmatory analysis will be done on the next day.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार): मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने इन्टरवल में आता है . . .

श्री उपसभापति : अभी आया है, पहली बार।

श्री शिव चन्द झा : कितने इन्टरवल पर आता रहेगा। चार महीने, छः महीने, साल, दो साल? फिर बन्द हो जायेगा।

श्री उपसभापति : अभी तो आया है।

श्री शिव चन्द्र झा : पहली दफा आया है। तारापुर का मामला जब बिगड़ा तब कुछ रास्ता निकला, लेकिन पहली बार कन्साइनमेन्ट आई, यह अच्छी बात है। लेकिन कितने इन्टरवल पर आयेगी यह आप हम को बतायें?

श्री उपसभापति : यहां कहां तक बता पायेंगे :

RESOLUTION RE. LEGISLATION FOR RECURITMENT, PROMOTION ETC: OF GOVERNMENT EMPLOYEES INCLUDING EMPLOYEES OF PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURES—*Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Kriahna Mohan. Not there. Shri Janardhanam. He has to go. Please finish in ten minutes. He has to catch the plane.

SHRI A.P. JANARDHANAM (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman. The mover of the Resolution has given, from his own experience, the troubles and tribulations of the Government employees who are suffering and has given us all the woes. He has been an employee who had been victimised and it was a very moving speech. Unless the employees are contented, nothing can be done. But in our country, there is absence of dedication, there is nipotism, there is short-sightedness, there is muishness, there is passing of buck to others. There are so many troubles.

Another thing, in our country we do not recognise that feelings are more vital than formulas. We think that if we are in a superior berth, others are servile to us, others are bound to work for us. The human touch in many places is woefully lacking. We know the difficulties which we experience from red tape. All these things have to be taken into consideration.

Studying about conditions of civil services and about officials' position, I have come to know that the French civil Service is the best in the world. We should try to emulate that.

Our friend, the mover of the Resolution, has catalogued the grievances of the employees. The Committee should go into them. He has lamented about great disparities. Naturally sitting at home, if there is one private sector employee, one Central Govern-

[Shri A.P. Janardhanam]

ment employee and one State Government employee, all the three will be at loggerheads and they will all be sitting and accusing each other and cursing their position. All this will have to be removed. We speak of Dr. Ambedkar We pointify about Mahatma Gandhi. But where have we gone ? People some to be dissatisfied every where. These things have to be tackled. For that we should have sincerity. And sincerity should begin from the legislatures. The politicians have to be very sincere. Creed, deed and word should be one. The Committee, I think, will therefore consider all these things. It is a highily technical subject.

My habit is to draw inspiration and, of course, on facts, from previous speakers. Because I have to rush up, I knew only this. We have to tackle all these things seriously. Since thirty-five years we have bungled because we have not been serious about the lives of those among whom we are cast. We will try to better their lot, we will put shoulder to the wheel and try to get them out of the morass into which they have got.

Thank you, Sir.

श्री शिव चन्द्र झा: (बिहार) उपसभापति महोदय, जहां तक सुकुल जी का संकल्प है, इसमे तो कोई बड़ा एतराज नहीं हो सकता है कि कानून बने इनेक्टमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाइज पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्ज के कर्मचारियों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोमोशन वगैरह का कानून बने लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह इनेक्टमेंट या कानन अब तक क्यों नहीं बना ? जमींदारी एबोलीशन हुआ उसके पीछे एक विचार था पहले नेताओं के सामने कि हम इसका एबोलीशन करेंगे जब यह मौका हम को मिलेगा। देश के आजाद होते ही इसका खात्मा किया । बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ उसके पीछे एक विचार था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का विचार था। अब यह जो चाहते हैं कि सेलेरीड सरकारी कर्मचारियों वगैरह के जो यहां के हैं ऐसा कानून उनके लिए आ सके, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कानून अब तक क्यों नही आ सका ? मेरा कहना यह है कि यह इसलिए नहीं आ सका क्योंकि सरकार के सामने कोई विचार है ही नही कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पलाइज की रिक्रूटमेंट प्रोमोशन वगैरह का कोई एक्ट हो। यह तो विचार-विहीन सरकार है। सुकुल जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्धारण दिया ।

यह प्रेक्टिकल है, फीजिबल है, यह सब बातें हैं पंडित जी की बहुत हमदर्दी थी। आप सुन लीजिये जरा। जिस समय सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाइज की 1960 में देशव्यापी हड़ताल हुई थी। उस समय गोविन्द वल्लभ पन्त जी होम मिनिस्टर थे पंडित जी प्रधानमंत्री थे। पार्लियामेंट में लोकसभा में पाइलट इम्पलाइज की तरफ से मामला उठाने वाले नाथपाई जी थे। नाथपाई ने जोरशोर से भाषण किया 1960 में तो पंडित जी ने उसके जवाब में क्या कहा--

> "They wanted to ride a tiger but they connot ride even a donkey".

पंडित जी का यह एक्सप्रेशन है पार्लियामेंट में कि हम इनको रोकेंगे और इसेंशियल सर्विसिज मेंटेनेंस एक्ट पास हुआ। तुरंत आर्डिनेंस जारी हुआ ।

> "They wanted to ride a tiger, but they cannot ride even a donkey".

पंडित जी ने उनको पाइलट किया, इससे उनकी महानता पर कोई आक्षेप नहीं आता। वह रहे नही यदि आज तक वह रहते तो कुछ नक्शा देश का दूसरा हो जाता लेकिन यह किस लिये नही हुआ क्योंकि सरकार के सामने कोई विचार

ही नहीं है कि वेज अर्नर्ज या डिसपेरिटी की बात है। डिसपेरिटी इन इनकम इन सब के मुत्तालिक कोई नियम बने इसके लिये आपका कोई दर्शन ही नही रहा। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाइज या जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर्ज के इम्पलाइज है इतने से ही बात खत्म नहीं हो जाती है आपको आमदनी के मुत्तालिक विचार लाना होगा, सोचना होगा। देश में जो आमदनी के तफर्के है, इसके संदर्भ में आपको निपटाना होगा लेकिन क्योंकि इनकम के मुत्तालिक कोई विचार ही नही है। बीस सूत्री कार्यक्रम की दुहाई दी जाती है लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम, थोड़ी देर के लिये इन पंच वर्षीय योजनाओं से क्या नतीजा निकला है। वही नतीजा निकला है। अभी सिर पीट रहे है कि पार्लियामेंट के इम्पलाइज स्टेट लेजिस्लेचर्ज के इम्पलाइज के लिये प्रोमोशन वगैरह के लिये रिक्रूटमेंट की व्यवस्था के लिये इंतजाम ही नही है। सिर पीट रहे हैं। ये पार्लियामेंट के जो इम्पलाइज है, एक छोटी सी बात है एम० पीज० के रहने के लिये आवास का इंतजाम हो सकता है, इनके लिये फ्लैट नहीं बन सकते हैं क्या? क्या यह असम्भव बात है? मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे एम० पीज० फ्लैट्स दोनो तरफ बने हुए हैं, पार्लियामेंट के कितने इम्पलाइज है जिनके रहने के लिये क्वार्टर्ज की व्यवस्था है? क्या यह असंभव है। कौन मुश्किल बात है। आज कल की मंहगाई के समय में उनके रिक्रूटमेंट और प्रोमोशन के नियम बदले, क्या इसके लिये पार्लियामेंट में बहस करने की जरूरत हो सकती है? जरूरत इसके पीछे भावना और विचारों की है और जो कि इस सरकार के पास नही है। सरकार विचारा-हीन और दर्शनहीन है। यह इनके पास नहीं है।

वेज अर्नर के मुताबिक वेज फिलासफी नही है। यदि आप और कुछ नही करना चाहते है तो दो ही काम आप कर दें और चीजें अलग लगा दें। नम्बर एक, जो इन्कम डिसपैरिटी सारे समाज में है उस बात को आप पकड़े, उसका झंडा बुलंद करे। ये सबके सब उसमें आ जायेंगे। सब निपटारा हो जायेगा। एक ओर दस के अनुपात में नारा लगा दें, सब हल हो जायेगा। नहीं, तो फिर इनको हड़ताल करने का अधिकार दे दें। राइट टु स्ट्राइक हर इम्प्लायी को या हर नागरिक को हो, यह फण्डामेंटल राइट होना चाहिये। आप संविधान की दुहाई देते है। कांस्टीटयूशन में बहुत परिवर्तन की जरूरत है। जैसे राइट टु वर्क है, राइट टु इन्फारमेशन है, राइट टु स्पीच है, उसी तरह राइट टु स्ट्राइक भी जरूरी है। आप केन्द्रीय कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार दे दे, कांस्टीटयूशन में दे दें तो एक मिनट में निपटारा हो जायेगा। क्या आप तैयार है? क्या आप उनको कांस्टीट्यूशन राइट, हड़ताल करने का अधिकार देंगे? सवाल अब उठता है कि जहां वह बात उठाते है आप कहेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद करो। राजनीतिक लोग चला येंगे तो कहेंगे मोटीवेटेड है, अपना पोलिटिकल हिसाब किताब कर रहे हैं। पटियाला की गोली की बात आज हम लोगों ने उठाई जिसमें जनता, जिला पार्टी के अध्यक्ष का लड़का मारा गया तो आपने समझा कि ये लोग पोलिटिकलाइज कर रहे हैं। तुरंत इसमें यह बात ...

श्री उपसभापति: उन्होंने तो नहीं कहा, डाक्टर सिद्धू ने तो नहीं कहा।

श्री शिव चन्द्र झा: मैंने कहा था, जब अखबार में बात आई। जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का लडका है अशोक

[श्री शिवचन्द्र झा]
कुमार । तो सवाल यह है कि यह सब दर्शन आपका नहीं है ।

श्री उपसभापति : रिजाल्यूशन पर बोलिये ।

श्री शिव चन्द्र झा : वह अपना वक्तव्य देंगे जहां वह डिसटर्ब करें **(व्यवधान)** तो आप उनको मदद कीजिय हमको डिस्टर्ब करिये **(व्यवधान)**

उप सभापति : नहीं रिजोलूशन पर बोलिये वह कह रहे हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : तो शुकुल जी, म कहना चाहता हूं कि ये दो विचार यदि आप पकड़ लें तो समाज में जो डिसपरिटी है, जिसमें ये लोग भी आ जाते हैं, वह खत्म हो जायेगी । इसके मुताबिक एक दर्शन और एक राष्ट्रीय नीति हो और वह नीति यही है कि मिनिमम और मैक्सीमम का फैसला हो जाये । मिनिमम एक और मैक्सीमम दस । उसी अनुपात में सब हों, राष्ट्रपति से लेकर खेतिहर मजदर और इम्प्लायी तक । यदि ये असमर्थ है ऐसा करने में तो कम से कम संघर्ष के लिये उनको संवैधानिक अधिकार आप दे दें । बस ये ही दो बातें आप कर ले । उसमें आपकी जो बाते है वे सब आ जायेंगी । ये बाते यदि नहीं होती हैं तब आप मोटीवेटेड हैं । प्राब्लम को टिकर करने के लिए ।

हम लोगों की बात छोड़ दीजिये, लेकिन सरकार इस को मान ले । सरकार नहीं मानेगी । यह इसलिये नहीं मानेगी कि सरकार पर रिफलेक्शन पड़ता है कि यह सरकार निकम्मी है । चूंकि अपने पार्लियामेंट के इम्प्लायीज के बारे में उनकी तनख्वाह और वेतनों के बारे में भी आज तक कोई कानन नही बना सकी । यह उन पर रिफलेक्शन है । यह निकम्मी है ऐसा वह कबूल नही करेगी । इसलिये नहीं मानेगी । लेकिन इसके पीछे दर्शन यदि आप कार्यान्वित कराना चाहते हैं तो इनकम सीलिंग की बात उठा दें । कांस्टीट्यूशन में फण्डामेंटल परिवर्तन करें । इन शब्दों के साथ म इसका समर्थन ही करता हूं । यही बात अगर हो जाये तो इसमें कोई शक नही कि समस्या हल हो जायेगी । लेकिन साथ साथ यह भी कहता हूं कि यह भी सरकार नहीं मानेगी ?

SHRI B. KRISHNA MOHAN (Andhra Pradesh) : I thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me the opportunity to support the Resolution moved by my good friend, Mr. Sukul. Not only myself but the entire House joins in congratulating him for moving this very good Resolution.

While associating myself with the views expressed by Mr. Sukul, since he has covered the entire ground, I will confine my views to one or two points.

He has rightly pointed that Parliament enacts laws, the judiciary interprets them and the executive carries out the laws of the Government. I am one of those who firmly believe that for the successful running of Parliament or the successful running of the judiciary or the successful running of the Government, much depends upon the confidence it enjoys from the employees. The matter of service conditions, the matter of recruitment, the matter of emoluments differ from the executive to the judiciary and to Parliament. There is no uniform set of rules in the matter of recruitment of the Government employees, the employees of the judiciary and the employees of Parliament. The recruitment rules also differ from one State to another. It is high time that the Government should come with a piece of legislation making uniform service conditions, making uniform recruitment rules of

all the Government employ, of all the Parliament employees, of all the judiciary employees, whether they belong to the Centre or they belong to the States.

According to the provisions in article 98(2) of the Constitution, Sir, Parliament may by law regulate the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of the either Houses of Parliament. Inspite of getting the Independence and having got the Constitution for so many years, no law has been passed for regulating the service of the employees of Parliament, Sir. The rules of recruitment as far as Parliament employees are concerned, were regulated by the Presidential Order under article 98 (3).

As you are aware, there are genuine grievances of the employees of Parliament, both the Houses of Parliament. When the Third Pay Commission was appointed, they wanted to give certain memoranda to the Pay Commission, but they were not taken into consideration on the ground that they did not come under the definition of the Central Government employees.

[The Vice-Chairman (Dr. Shrimati Najma Heptulla) in the Chair]

As rightly pointed out by my good friend, Mr. Sukul, a Pay Commission was appointed by the Chairmen of both the Houses in 1973, and some of the recommendations of that Commission have not so far been implemented as far as Rajya Sabha is concerned. Sir, right from the Secretary-General upto the lowest category, they work under constraints and odd conditions, and they should be given special conditions because they cannot be equated with the Government employees. I may also point out a glaring anomaly as far as the pay-scales of certain categories of the employees of Parliament are concerned. The Assistant Editors who are working in the scale starting from Rs. 650, have to wait for nearly 12 to 15 years to get promotion to the post of Editor starting with the basic pay of Rs. 70 . That is the greatest anomaly. Sir, the Typists, the Stenographers and others working in Parliament Secretariat get a meagre pay when compared to their counterparts working in the public sector undertakings, in the Reserve Bank of India and the State Bank of India.

Apart from these things, common recruitment conditions should be there. The conditions should be on par for all the State Government employees also. A common procedure should be evolved for the matter of recruitment in all the States, Sir. The recruitment conditions, the emoluments, the pay-scales differ from one State to another. So, a uniform set of service conditions, a uniform set of recruitment rules should be evolved for all the States making them on par with the Central Government employees.

I believe, either the Central Government employees or the State Government employees or the employees of the judiciary or the employees of Parliament should not work under frustration. With a good sense of duty and with a moral sense of responsibility they have to work. We have to give them the necessary pay-scales, the necessary promotion. We have to give them the necessary service conditions and other benefits. I may quote an example, Madam, from Andhra Pradesh. When Dr. Chenna Reddy was the Chief Minister of Andhra Pradesh in 1978, he appointed a Pay Commission, that is, the Krishnaswamy Pay Commission. That Krishnaswamy Pay Commission made a recommendation that the age of retirement should be enhanced from 55 to 58 bringing it on par with the Central Government employees. The recommendations of the Krishnaswamy Pay Commission were taken into consideration and the Chenna Reddy Government raised the age of retirement of the Government employees from 55 to 58 bringing them on par with the Central Government emplo-

ttook

[Shri B. Krishna Mghan]

charge in January, the first drastic action taken by them was reducing the age of retirement of the Government employees from 58 to 55. It is an arbitaray decision. The Government employees were not consulted. The services associations were not consulted. If such is the state of affairs, how will the Government employees cooperate with the State Government and how will the decisions of the Government be properly implemented ! Madam, they can reduce the age of retirement by an executive order; that is the writ of the Government. But while taking the decision, the employees should be consulted. At least should have said, "All right, we are reducing the age of retirement from 58 to 55. We are giving you two months' time or there months' time. You mentally prepare yourself for retirement". Even that opportunity was not given to the employees. By one stroke of pen the age of retirement was reduced from 58 to 55. Of courses, they have gone in a writ petition to the Supreme Court. It is *sub judice*. So I do not want to go into the details. But the Supreme Court has asked the State Government to pay another three month's salary to those who have been retired. Nearly 20,000 employees were thrown out of jobs because of this order of the State Government, When Mr.M.G.Ramachandran visited Hyderabad on the 18th April to sign the agreement on the sharing of Krishna waters between Andhra Pradesh and Tamil Nadu, there was a demonstration of nearly 20,000 employees before the Andhra Pradesh Secretariat. It was the first time in the history of Andhra Pradesh Government that nearly20,000 employees from the nook and corner, of the State demonstarated and carried placards against the State Chief Minister. If such is the attitude of the Government employees, how can the Government run? The Government should win the confidence of the employees and should inculctge in them a sense of duty. They should take them into cinfidence and provide them all amenities and proper emoluments.

With these few words, I fully and wholeheartedly support the Resolution moved by Mr. Sukul. I hope the entire House agree with him and the Resolution will be passed unanimously.

SHRI K. MOHANAN : Madam Vice-Chairman, I would like to congratulate the mover of this Resolution, my esteemed friend, Mr. Sukul. I am not calling it an open confession before this august House, but with integrity and sincerity he has moved this Resolution and I am taking the Resolution in this good spirit. In many departments, even now the serivce rules. including the mode of recruitment and promotion, are incomplete. For example, Parliament is the law-making body, The employees who are working here are one of the most aggrieved parties of the present state of affairs. The mover of the Resolution has already mentioned about the constitutional provision concerning Parliament Secretariat. In this this connection, I would like to invite to the attention of the Government to article 98 (2) of the Constitution which reads :

> "Parliament may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of either House of Parliament".

The Parl ament Secretariat is an independent Secretariat where the staff have to function independently without fear or favour from anybody. That is why the Constitution has given it a separate status. The employees here have no union or association to act as a bargaining agency. So it is all the more necessary that they have to be looked after well and their grievances have to be removed. It is understood that no separate law has been enacted in spite of the above constitutional provision to regulate the service conditior which are even now governed by a se of rules framed probably in accordance with clause (3) of article 98. I do not wan

to go into the details of the grievances of the secretarial staff of this Parliament. I just touch upon this subject in general and request the Government to look into the matter very seriously without much delay. Not only in Parliament Secretariat but also in many other departments, there is no uniformity of service rules and many of them are too flexible and employees are governed simply by executive orders. In may departments there is the practice of provisional appointment, by passing the PSC, employment exchanges or such other statutory bodies which are really competent to deal with such appointments. After provisional appointment made out of the way, such employees may be inducted into the regular service at the whims and fancies of the Government and the superior officers. Not only in the case of appointment but also in the case of promotion, in many instances promotions are provisional and confirmation and regularisation is not at all done through the statutory process in many departments in many States. Departmental Promotion Committees are not functioning properly, In many cases they are not at all functioning. That is the experience. The disparties and anomalies in serivce conditions including pay-scales are demoralising factors still prevailing in many departments. In many cases there is no parity between employees doing the same work in different departments in different States. There is a wide gap between institution and institution and State and State. Even in the case of retirement benefits and such other things, thing is difference from State to State as well as the Centre. It is my suggestion that a uniform recruitment policy must be adopted and uniform service rules must be framed for each and every department and they should be strictly adhered to. Recently the Prime Minister issued an order to terminate the services of all officers who have been continuing in serivce after their superannuation. I am sorry to say that she herself has defeated the very same order by giving extension to so many officers in her own Secretariat. This is not a healthy approach towards the service problems and the administrative problems of the State. The confidential record system is a barbarous system. It was the creation of the British rulers with the sole aim of creating a slavish cadre in the service. West Bengal abolished this system and they have democratised the service to a great extent by conceding the fundamental right of the employees to strike. Government employees at the Centre and in various State are still agitating for better service conditions and better treatment. But I am sorry again to note that even now the Government is in frantic search for more weapons to suppress the movement of teachers, hospital employees and such other Government employees under its various institutions. I am not going into the details of the various disparities and anomalies prevailing in the various departments and services. My only request to the Government is that they should come forward with a specific set of rules for every department in the Central Service and a guideline to the States how to modify the present service rules and how to implement them without any injustice towards anyone. With these words I conclude.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): Madam Vice-Chairman, I think the Resolution which has been moved by my esteemed friend, Mr. Sukul, is of reat importance not only for those for those for whom it is meant but also for healthy and effective public administration. The mover has elaborately dealt with the subject in all its different aspects and I propose withn ithe time at my disposal to confine myself to a few legal propositions and make a few submissions to the honourable the Home Minister who is present in the House for his kind consideration.

[Shri Sanker Prasad Mitra

The first article of relevance to this Resolution is article 43 in the Directive Principles of the Constitution in Part IV. It is an article which envisages legislation to secure work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities to all workers, agricultural, industrial or otherwise.

There are three Supreme Court Judgements and one Allahabad High Court Judgement which ought to be referred to in this connection and a fourth Judgement of Supreme Court which was delivered only yesterday.

I am referring to the Supreme Court decision in Chandra Bhavan State of Mysore reported in AIR 1970 Supreme Court, at page 2042, paragraphs 10 and 13. The next one is the Allahabad High Court Judgement in Eveready Company vs. Labour Court, reported in AIR 1962 Allahabad 497. From these Judgement you will find that article 43 of the Constitution was relied on to uphold the "reasonableness" of restrictions imposed by the Minimum Wages Act, 1948 with reference to the Fundamental Right to carry on business under article 19 (1) (g) of the Constitution and to condemn unfair labour practices.

There are two other judgements of the Supreme Court. One is the Judgement in Pathumma vs. State of Kerala reported in AIR 1978 Supreme Court 771, paragraph 14 onwards, and the other is the Judgement in State of Bombay vs. Balsara, reported in 1951 Supreme Court Reported 628.

In these two Judgements it has been said that the restrictions imposed for securing the objects enshrined in the Directive Priniciples of the Constitution may be regarded as reasonable restrictions within the meaning of clauses (2) to (6) of Article 19.

And yesterday the Supreme Court has delivered a Judgement saying that the Minimum Wages Act should be immediately applied to workers in the coal mines in Singhum district of Bihar. Starting from Article 32 which is in the Directive Principles of the Constitution and in the founding fathers of our Constitution had indicated how the workers in different fields should be treated, we may pass on to Articles 98, 187 and 309 of the Constitution. These articles have already been referred to by the mover of the Resolution and I do not propose to repeat what he has said. But I respectfully submit to you that in article 98 and in article 187 there are specific provisions for the Parliament and the State legislatures, as the case may be, to regulate by law the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Secretarial staff of either Houses of Parliament or State Ligislatures.

Until such legislation comes into force, there are provisions, certain temporary or transitional rules, which are to be observed and, as far as I know, it is these temporary or transitional rules which are in operation with regard to this class of employees. Therefore, regulation by legislative enactments of the service conditions of the secretariat staff of Parliament and the State Legislatures is the Permanent feature which the founding-fathers had contemplated; and it is a pity that although the Constitution came into force on the 26th January 1950, up till now, no such legislation has been brought into force. There are similar provisions under article 309 of the Constitution for recruitment and other service conditions of other Government employees. Here also the rules that are now force are temporary or transitional rules because article 309 gives power to the appropriate legislature to regulate by law the recruitment and conditions of service of the persons concerned. Again, I say that what was contemplated to be the permanent provisions should be brought into force as early as possible. Now, Madam, my submissions to the honourable Minister of State for Home Affairs are three:

My first submission is that the issue of legislation under article 98, article 187 and article 309 should be immediately referred to the Law Commission.

My second submission to him is that the Law Commission should be requested to submit its report on the legislations to be enacted within a specified period of time.

And, Madam, my third submission to him is that the Law Commission's report should not be kept in the cold storage, as is usually done, but the Government should proceed to implement that report. The reasons why I am saying that it should be referred to the Law Commission are two: Madam, I wish to draw your attention to the opening words of article 309. The opening words are: "Subject to the provisions of the Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State: ...". Now, these words "subject to the provisions of the Constitution" mean that whatever legislation is framed, that legislation must be subject to the provisions, for instance, of Articles 14, 15, 16, 19, 229, 234, 310 and 311 of the Constitution.

Madam, my second reason is that Article 311 provides for an elaborate procedure for dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State. There is a huge volume of case laws, a large number of cases which have given valuable rights to the persons concerned. And these cases decided either by the Supreme Court or by the different High Courts of India have to be taken into account, have to be taken into consideration before framing legislations under articles, 98, 187 and 309. For these two reasons, I made those three submissions to the hon. Minister for Home Affairs. And it is my fervent hope that he would very kindly accede to my requests.

With these words, I support the Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : We can have only one more speaker because at about 4.20 p.m. the Minister will reply, and then Mr. Sukul also would like to reply.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra) : The discussion can go upto 4.30 p.m.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Why 4.20? Make it 4.21.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] All right, 4.21 p.m. (*Interruptions*)

We have to adjourn at 5 o'clock today.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : There is no Half-an-Hour Discussion. We can go beyond 5 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : Deputy Chairman Saheb told me that we have to adjourn at 5 o'clock. Now Shri Kalraj Mishra.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, श्री सुकुल जी ने जो यहां पर संकल्प उपस्थित किया है उसकी मूल भावना का मैं स्वागत करता हूं और मैं स्वयं यह अनुभव करता हूं कि जिस विषय के बारे में बहुत पहले ही संसद् के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए था और केवल आकर्षित ही नही होना चाहिए था, अपितु आज जिस प्रकार के प्रस्ताव की अपेक्षा है उस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करके उसके अनुसार कानून की व्यवस्था करने की दृष्टि से संसद् का निर्देश प्राप्त करना चाहिए था वह नही हो पाया है।

[श्री कलराज मिश्र]

[उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) पीठासीन हुए]

यह प्रस्ताव गैर सरकारी प्रस्ताव के रूप में आज सुकुल जी ने उपस्थित किया है । इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमन् संविधान की मूल भावना यह है कि पूरे देश के अन्दर सेवारत कर्मचारियों के लिए चाहे वे केन्द्र में काम करते हों या राज्यों में काम करते हों, उनके लिए एक सामान्य नियमावली होनी चाहिए । उनके लिए सामान्य सेवा शर्तों का निर्माण होना चाहिए । उसके अनुसार उनकी भर्ती उनकी पदोन्नति और उनके वेतन में एक नियमितता का निर्माण होना चाहिए । यह संविधान की भावना थी जिसको कानून का रूप देकर सभी लोगों को एक सामान्य नियमों के अन्दर लाया जाना चाहिए था । उनके मन के अन्दर सुरक्षा की भावना प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता होनी चाहिए । लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नही हो पाया । आज यह प्रस्ताव सामने आया है । मैं यह अनुभव करता हूं कि आज देश में कर्मचारियों के अन्दर असंतोष की भावना का निर्माण हो रहा है। इससे उनके अन्दर कभी-कभी सरकार से लड़ने की स्थिति पैदा होती है। इसके पीछे कारण कौन से होते है इसको श्री सुकुल जी ने भी अपने तरीके से रखने की कोशिश की और उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि उनके बारे में उनकी सेवा नियमावली के अन्दर या आचार संहिता के अन्दर जो भी समय-समय पर चीजें निर्धारित की गई है उसमे यह बात कही गई है कि जो भी राज्य या केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है वह अपने असन्तोष को व्यक्त करने के लिये व्यक्तिगत तौर पर सरकार की नीतियों जो इस संबंध में बनाई गई हैं उनकी आलोचना भी नहीं कर सकता । अगर उनकी वह आलोचना करता है तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही हो जायेगी । अपनी बातों को भी व्यक्तिगत तौर पर, अपने असन्तोष को भी ठीक ढंग से उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता है और उसका नतीजा हुआ है कि कर्मचारियों के संगठन बने हैं और वह संगठन ट्रेड यूनियन के माध्यम से उनके असन्तोष को प्रकट करता है । श्रीमन् मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका इन तीनों के माध्यम से जिस भी तरीके से हो कर्मचारियों के संबंध में समान रूप से कानून बनाने की आवश्यकता है। इसको अविलम्ब बनाया जाय । सरकार यह अभी तक नहीं बना पाई इसके लिये निश्चित रूप से वह दोषी हो जाती है । जिसकी भी सरकार रही होगी । यह मैं नहीं कहता कि यह सरकार है, वह सरकार है, इसका सवाल नहीं है । लेकिन कुछ भी इस दिशा में जिस प्रकार से सोचा जाना चाहिए था उस प्रकार सोचा नही गया, यह हम अनुभव करते हैं । क्योंकि श्रीमन् जहां हम राज्य और केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचार करते हैं उसमें एक बात और मूल रूप से उभर कर सामने आती है, इस बारे में हमारे कुछ मित्रों ने उस तरफ संकेत करने की कोशिश की है । मैं भी उसको दोहराना चाहूंगा और वह यह है कि राज्य में उसी स्थान पर उसी प्रकार का काम करने वाले कर्मचारियों का कुछ दूसरा वेतन है और केन्द्र के कर्मचारी, जो उसी प्रकार का काम करता है उनका दूसरा वेतन है । भिन्न-भिन्न राज्यो में समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन के अन्दर विषमत हैं,यें उनकी

सुविधायों के अंदर विषमतायें हैं, उनको पदोन्नति के अन्दर विषमतायें हैं । इसी तरह से केन्द्रीय सरकार के कमचारी जो कि वही काम करते है उनका राज्य के कर्मचारियों से वेतन और अन्य सुविधाओं में, जो कि वही काम करते हैं जबर्दस्त विषमतायें हैं । कई राज्यों के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से कम वेतन पाते हैं और कहीं उनसे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं । मैं चाहता हूं कि ये विषमतायें समाप्त हों और समान काम के लिये समान वेतन, समान सुविधायें और समान पदोन्नति इसे मान्यता प्रदान की जाय, कानून के माध्यम से, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

साथ ही साथ श्रीमन्, जैसा कि कई सम्मानित सदस्यों ने इस बात की तरफ संकेत किया कि और संसद् के जो कर्मचारी हैं ये रात दिन यहां काम करते हैं । लेकिन उनके बारे में भी आज तक कोई नियमावली नहीं बन पाई और वे बेचारे भी अपनी बात को सामने नहीं रख सकते, नहीं कह सकसे संविधान के लागू होने के 35 वर्ष बाद भी संविधान के अनुच्छेद 98(2) के प्रावधानों को सरकार अभी तक भी लागू नही कर पाई है । इस अनुच्छेद का संबंध संसद् की दोनों सभाओं के कर्मचारियों के संबंध में सेवा की शर्ते तथा नियम बनाने से है । संविधान के अनुच्छेद 98(2) में कहा गया है :

"संसद्, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन के सांचविक कर्मचारी वृन्द मे भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी ।"

अभी तक संसद के दोनों सदनों के सचिवालय के कर्मचारियों की सेवायें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 98(3) के अधीन बनाये गये नियमों से नियंत्रित होती है । सरकार को अनुच्छेद 98(2) के अधीन तुरन्त एक विस्तृत विधेयक लाना चाहिये ताकि इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का समुचित रूप से विनियमित हो सके ।

संसद के कर्मचारियों की अजीब स्थिति है जब कभी भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये किसी वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसके सामने ये कर्मचारी अपना ज्ञापन नहीं दे सकते हैं । परन्तु बाद में इस आयोग की जिन सिफारिशों को सरकार स्वीकार कर लेती है उन्हें इन कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाता है । इस प्रकार इनको अपनी बात कहने का कहीं भी मौका नहीं दिया जाता है । पिछले 33 वर्षों के दौरान केवल एक बार संसद् कर्मचारियों के लिये संसद् की एक वेतन समिति का गठन किया गया था । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1971 में दिया था परन्तु अफसोस इस बात का है कि हालांकि यह कमेटी लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के अध्यक्ष, दोनों सदनों के अध्यक्षों. . . . (**समय की घंटी**) अभी थोड़ा सा है, समाप्त कर रहा हूं, द्वारा गठित की गई थी । परन्तु उस समिति के प्रतिवेदन पर आज तक संसद् में चर्चा नहीं हुई है । इसलिये इस मौके का लाभ उठाकर मैं मांग करता हूं कि उस समिति के प्रतिवेदन पर संसद् में तुरन्त चर्चा करायी जाए । इसके अतिरिक्त मैं यह भी मांग करता हूं कि जब कि सरकार ने अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये चौथे वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है इसलिये संसद् के सचिवालय के कर्मचारियों के लिये भी तुरन्त वेतन समिति का गठन किया जाए जो इनके वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का अध्ययन कर के

[श्री कलराज मिश्र]

अपनी सिफारिशें दें जिस पर संसद् के दोनों सदन चर्चा कर सकें।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया): जरा शार्ट कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दो मैम्बर्स और जो इस पर बोलने वाले हैं उनको अक्कमोडेट करूं।

श्री कलराज मिश्र : श्रीमन्, सरकारी कर्मचारियों में कई पदों के वेतनमान इस प्रकार हैं कि एक वेतनमान से पदोन्नति पाकर दूसरे वेतनमान में जाने वाले कर्मचारी को कोई विशेष वित्तीय लाभ नहीं होता। उदाहरण के लिये संसद् सचिवालयों में सहायक संपादकों और संपादकों के वेतनमान को लिया जा सकता है। सहायक सपादकों का वेतनमान 650 रुपये से 1200 रुपये तक का है जबकि संपादक का वेतनमान 700 से 1300 तक है। एक सहायक संपादक को संपादक बनने के लिये 10 से 15 साल तक लग जाते हैं। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि इतनी अवधि के बाद भी उन्हें वित्तीय लाभ कोई नहीं होता। इसलिये इस विषमता को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए और सहायक संपादकों और संपादकों के वेतनमानों में संशोधन किया जाना चाहिये। क्योंकि इनके वेतनमान इसी प्रकार का काम करने वाले अन्य मंत्रालयों के कर्मचारियों से काफी कम है। जबकि यहां के कर्मचारियों को उनसे कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। इनके काम की सराहना तो सदन में कई बार हो चुकी है। अनुवाद कार्य को ही लीजिये, गृह मंत्रालय तथा हिन्दी निदेशालय में एक अनुवादक को करीब तीन पृष्ठ जबकि संसदीय सचिवालयों में प्रतिदिन आठ पृष्ठों का अनुवाद करना पड़ता है। काम का कोटा इतना अधिक होने के कारण सुयोग्य अनुवादक संसदीय सचिवालयों में आना पसन्द नहीं करते। एक वर्ष में तीन-तीन बार परीक्षा लिये जाने के बावजूद प रिक्त स्थान नहीं भरे जा सके जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी में वाद-विवाद की रिपोर्ट छप कर हम तक पहुंचने में एक वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है।

श्रीमन्, साथ ही मैं और यह भी कहना चाहूंगा जैसे कि रिपोर्टर्ज हैं, इन लोगों की भी वही स्थिति है। यह संसदीय रिपोर्ट को तैयार करते हैं लेकिन उनकी पदोन्नति का कहीं अवसर ही नहीं है। जिस पद पर वे नियुक्त होते हैं अन्त में उसी पद पर वे अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। मेरा यह कहना है कि यहां के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एजे भी एक सी नहीं है। यहां कुछ तो 60 वर्ष में रिटायर होंगे लेकिन बीच वाले जो हैं उनको 58 वर्ष में हीं रिटायर कर दिया जायेगा। मेरा यह कहना है कि संसद के जो कर्मचारी हैं उनके लिये भी एक निश्चित रूप से एक-समान नियमावली बनानी चाहिए। उनकी जो समिति बनी थी उसके प्रतिवेदन को रखना चाहिए और लेजिस्लेशन उस प्रकार का पास कर के इनको भी उसी प्रकार की सुविधायें प्रदान करनी चाहिये। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से जो श्री सुकुल जी ने रखा है, आग्रह करूंगा कि इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिये और इतना कह कर सुकुल जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसकी भावना का समर्थन करता हूं और सुकुल जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा जो यह महत्वपूर्ण संकल्प लाये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने यह बात रखी, मैं भी आग्रह करूंगा ला कमीशन को कानून बनाने की दृष्टि से संविधान की धाराओं को परिभाषित करने की दृष्टि से इस कार्य को सौपना चाहिये ताकि जल्दी मे जल्दी विधेयक इस सम्बन्ध

में लाया जा सके, कानून बनाया जा सके, सारी विषमताओं को दूर करने की दृष्टि से व्यवस्था की जा सके।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA) : Really speaking, I have to call upon the Minister to reply. But there are two Members who have already given their names, Mr. Dhabe and Mr. Satyanarayan Reddy. Now, I do not mind calling upon both of you, provided you confine yourself to five minutes each. You must cooperate with me.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : I will take only five minutes.

The question which has been raised is very important. I support the Resolution, but I am doubtful whether the Parliament has got the powers under article 187 to regulate service conditions of the employees of the Parliament or even of the State Legislatures. I would like to know from the Minister one thing. There is an announcement that administrative tribunal will be constituted under article 322(a). I want to suggest that if under article 322(a) the administrative tribunal is constituted then the appeal may lie to Supreme Court and not to the High Court. Otherwise, every matter, every grievance, will to go the High Court and then to the Supreme Court which will take a long time. So, article 322(a) should be implemented in letter and spirit and this suggestion should be accepted.

So far as the government servant is concerned, the most important thing for him is job security, wage security, grievance settlement machinery and promotion. Fortunately, for the first time we are discussing Parliament staff. As the hon. Members pointed out, there is no promotion channel. Even after the people have served for a long time, they are not getting due promotion. Therefore, a rational promotional policy is very essential for giving incentive to the government servants. For the purpose of job satisfaction, for the purpose of their efficiency, it is necessary that 4 promotions are given to them. The Pay Commission has laid down that if any Government servant's interest in the job is to be kept up, at least 4 promotions in his service period should be given to him.

I fail to understand one more thing as to why the system of casual labour, temporary labour and contract workers should not be abolished. In many government offices, including railway undertakings, we find there is a tendency to appoint more and more workers on daily wages. Contract work is the new system which they have started. This system should be abolished. It is necessary that all government servants are given job security and the system of having temporary and contract labour should be abolished.

Lastly I want to say that 80 per cent of the people are given bonus. Today the practice all over the country or even all over the world—whether they are the socialist countries or the democratic countries—has been that for 12 months' work 13 months' wages are paid. Therefore, the Payment of Bonus Act should be amended so that statutorily it is paid to all the employees. There is no reason why it should not be paid to the Parliament staff. I fail to understand why the Parliament staff and other staff is not getting the bonus. I suggest to the Minister that this should be done.

My last point is, if there is a legislation on the service conditions of the government employees and others giving them job security, proper promotion channel, wage security, grievance settlement machinery which is essential for the successful functioning of government in a democratic country, it will go a long way in efficient functioning of the Government. So sir, if you want succesful functioning of the Parliament there should be specific legislation on the service conditions of the government employees and others.

श्री बी० सत्यानारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि मुकुल साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसके पीछे जो भावना है उसका समर्थन करते हुये मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहता हू कि इतने साल हो गए हिन्दुस्तान को आजाद हुए और कांस्टीट्यूशन को अमल में आये, इस लम्बे अरसे तक इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार ने क्यों नहीं कुछ सोचा। आज हम देश के अन्दर देखते हैं कि हर जगह यह विषमता है। केन्द्र में ही नहीं बल्कि हर राज्य में भी है। हम देखते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में आज हर कारखाने में हर जगह में लोगों को यह परेशानी है कि देश में सब को एक जैसा न्याय नहीं मिलता। जैसे कि आज बम्बई की मिलों मे हजारों लाखों की तादाद में मिल मजदूर हड़ताल पर हैं।

इसी तरह से अध्यापक है, उनकी हड़ताल होती है उनके बारे में भी कोई कुछ नहीं कहता है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरह का कोई कानून बनाने से पहले इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि केन्द्र में और राज्य में जितने कर्मचारी हैं उनके साथ एक सा वर्ताव हो, उनको समान सुविधाएं हों। मेरे ट्रेजरी बैंच के एक साथी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह तय किया है कि 58 साल से 53 साल की कर्मचारियों की एज लिमिट कर दी है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे लोगों का समर्थन था जो सरकार ने उचित समझा तथा यह काम किया। आज आप जानते ही हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद मे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। राज्य की जो पिछली सरकार थी वह इन सबको छोड गयी। लोगों को रोजगार का मौका नहीं था, कुछ काम नहीं था। तो उन सभी लोगों को रोजगार पहुंचाना था, काम देना था। चन्ना रेड्डी की सरकार ने 55 वर्ष से जो 58 वर्ष तक एज लिमिट बढ़ाया था और अब उसको घटा दिया है, कोई नई चीज नहीं की है... (**व्यवधान**) जब मैं बोल रहा हूं तो उनको बोलना नहीं चाहिये। तो यह कोई आरबिटरेरी डिसीजन नहीं है। इसको तो जनता का समर्थन है। यह जनता के समर्थन से ही हुआ है। यदि आरबिटरेरी डिसीजन होता, तो आंध्र प्रदेश में हल्ला मच जाता। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नाराज लोग डिमांस्ट्रेशन करते हैं। आप देखेंगे कि बंबई में लाखों की तादाद में डिमांस्ट्रेशन हुआ, यहां दिल्ली मे भी अध्यापकों ने लाखों की तादाद में डिमांसट्रेशन किया। वहां तो कुछ हजारों की तादाद में लोगों ने डिमांसट्रेशन किया। तो जो आम लोग हैं उनका समर्थन राज्य सरकार के साथ है। (समय की घंटी) मेरे कहने का मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश ने कोई आरबिटरेरी डिसीजन नही किया है। जो हजारों की तादाद में बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रेक्रूट करना है। कई इंजीनियर्स हैं, डाक्टर्स हैं, साइंटिस्ट्स है, सब लोगों को जो नौजवान हैं, जो अभी कालेज से निकले हैं, उनको रोजगार देना है, उनको नौकरी में पहुंचाना है। इसीलिये उन्होंने यह इंतजाम किया है और अच्छा काम किया है, उसको लोगों का समर्थन है।

इसके साथ-साथ मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह खेत मजदूर, जो लाखों की तादाद में गांवों में काम करते है, मिलो में जो काम करते है, कारखानों मे जो काम करने वाले हैं, इन लोगों की क्या हालत है ? इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुये सरकार को चाहिए

कि एक ऐसा कानून बनाये ताकि सब कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिहाज से मुआवजा मिले। मैं सरकार से चाहता हूं कि जैसे मित्रा साहब ने कहा कि एक वेज कमीशन बिठाना चाहिए ताकि इस विषमता को दूर किया जा सके और सारे देश को खुशहाल और ताकतवर बनाने के लिये एक ऐसे कानून की सख्त जरूरत है।

इसके बारे में सरकार कुछ निश्चय करे।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Member, Shri Sukul, who has moved this Resolution, has received more or less unanimous support from all sections of the House. So I have been put in a very difficult situation and I have to explain the various points that have been made out by the mover as well as by the various Members.

While moving the Resolution, Shri Sukul, who knows the problems of the employees very well, he having been an employee himself, and who has championed their cause for a number of years and suffered also championing their cause, has quoted some provisions of Art. 309 in support of his Resolution. Article 309 of the Constitution provides two alternative modes for prescribing the method of recruitment and conditions of service of Government servants namely--legislation and Presidential regulations. Similar privisions are contained in some other articles of the Constitutions also. The legal position is, when the Constitution provides for two alternative modes for a certain thing, it is not mandatory that one must be preferred to the other, or one is transitory or intermediate in nature and should be resorted to only for a limited period. The regulation-making powers of the President of India under the provision to Art. 309 cannot thus be said to be transitory or short-term and it is not obligatroy on the part of the Government to sponsor legislation for regulating the conditions of service.

Another point which the hon. Member has made out is that more than 30 years or so have passed since we framed our Constitution and dealt with, under various articles the service conditions to be regulated by the Government. So far as Government employees are concerned, this has been taken note of by the Government I may recall for the information of the Members of this House that this matter has come up several times before the House. And also, several committees have gone into this matter and ultimately they have come to the conclusion that the present system, that is, the present method of regulating the services of Government employees stands the test of time. First, the question of bringing forward a legislation before Parliament for regulating the conditions of service of Central Government employees as provided in article 309 of the Constitution was also a subject-matter of discussion in the Estimates Committee of Parliament and in the Committee of Petitions. It is true that no law as yet has been enacted to regulate the recruitment and conditions of service of Central Government employees as contemplated in article 309. At present, recruitment to the various Central services and posts is regulated by separate recruitment rules framed by the President in exercise of the powers conferred on him by the provisions of article 309. The conditions of service of Central Government employees are regulated by various sets of rules like the Fundamental and Supplementary Rules and Civil Service Regulations which were made under section 968 of the Government of India Act, 1919 and which continues in existence by virtue of article 319, and the Central Civil Service Leave Rules, Central Civil Service Pension Rules, Central Civil Service Conduct Rules, the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal)

[Shri P. Venkata Subbaiah]

Rules, etc., all of which derive their aurhority from the proviso of article 309. The question whether Acts of Parliament should be framed under article 309 to regulate the recruitment and conditions of service of Central Government employees was considered in 1950 soon after the Constitution came into force. It was found that the Government of India Act, 1935 also contained similar provisions in section 241 (5) thereof for the passing of Civil Services Acts by the Legislature to regulate the conditions of service of persons serving His Majesty in a civil capacity in India, but this provision could not be made use of till the present Constitution was adopted in 1950. After a protracted discussion it was decided in 1954 to continue to regulate service conditions by a regime of rules as it was found to be more convenient in practice. The Members of he House are also aware that the Administrative Reforms Commission went into the entire gamut of Government machinery and made important recommendations. The estimate Committee as well as the Committee on Petitions made certain recommendations. This was also considered by the Administrative Reforms Commission. The Commission recommended that the rules relating- to recruitment and other conditions of service of Government employees serving the Union may continue to be made by the President in exercise of the powers derived from the Constitution, and Government accepted this recommendation. The Government has had opportunities of examining the recommendations of the Estimates Committee and the Committe of petitions, as I have said earlier , in great detail and came to the following conclusions in the light of the recommendations made by these two Committees :

> "There are some Ministries and Departments which administer many cadres with different conditions of service, procedure of recruitment and promotion, etc. For example, the Ministry of Railways, Ministry of Communications, Ministry of Defence, etc., have a very large number of employees holding great variety of posts and the lower formations under these Ministries extend to every nook and corner of the country. These Ministries, to take only a few, operate a large number of recruitment rules and rules relating to services under their control, laying down the principles of seniority, confirmation, promotion,, etc., applicable to the various cadres of these services. It would be an almost impossible or, at least, impracticable task, to codify all these different rules into comprehensive legislation covering all the Central Government employees serving in different cadres of various services. In fact, the administrative machinery of the Government of India has grown so much in volume and complexity and the variety of the personnel serving the Government is also so very large that any effort to cover all of them by a single piece of legislation is fraught with numerous difficulties, making it a time-consuming and expensive exercise the result of which may not be commensurate with the time and money involved."

During these years, when the President has been framing rules in exercise of powers conferred by proviso to article 309, there has hardly been any occasion where a complaint has been made regarding the Government tinkering with the rules to the detriment of the Government employees. The framing of rules for the Government employees is a complicated process by itself requiring consultation with various Ministries and Departments, including the Ministry of Law, the Ministry of Finance, the Comptroller & Auditor General, UPSC, etc. Where the rules have the impact on a large number of Government employees, the matter is also discussed with the staff side of the National Council set up under